ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-1* February-2017
Innovation The Research Concept

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था : वर्तमान संदर्भ में

मांगीलाल जैन
व्याख्याता,
लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग,
मुलतानमल भीकचन्द छाजेड़ राजकीय महिला महाविद्यालय,
बाड़मेर

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था की नकदी पर निर्भरता बहुत अधिक है। वर्तमान में 95 प्रतिशत बैंकिंग से सम्बन्धित लेनदेन भारत में नकदी के माध्यम से ही होता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था होना सिद्धांत रूप से ठीक है, लेकिन नकद यानी नकदी का तोड़ निकालना इतना आसान भी नहीं है। मानव सभ्यता में वस्तु विनिमय के बाद से पैसे का चलन रहा है। नकदी से लेनदेन और आर्थिक व्यवहार को हतोत्साहित कर डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल जैसे डिजिटल तरीकों से भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल लेन–देन का लाभ अनपढ़ लोगों को कम और पढ़े–लिखे संपन्न लोगों को कहीं ज्यादा मिलेगा और इस तरह डिजिटल डिवाइड सामजिक, आर्थिक विषमता को गहराने में सहायक बनेगी। लेकिन नकदी–रहित अर्थव्यवस्था तक पहुँचने के लिए भारत को अभी भी लम्बी दूरी तय करनी है। आने वाले समय में कैशलेस इकोनॉमी का फायदा वित्तीय पूंजी को भी मिलने की सम्भावना है।

डिजिटल इंडिया विजन को हासिल करने और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में समर्थ है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपनाने का मुख्य औचित्य यह है कि इस व्यवस्था से सम्पूर्ण जीडीपी का रिकार्ड उत्पादन, वितरण व आय के रूप में रखा जाना संभव हो सकेगा। इस शोध पत्र में भारत के वर्तमान संदर्भ में कैशलेस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता, फायदे एवं प्रभावी कियान्वयन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां एवं उनके संभावित निराकरण का अध्ययन किया है।

मुख्य शब्द : कैशलेस, अर्थव्यवस्था, डिजिटल लेन–देन, इंडिया विजन

प्रस्तावना

देश में भ्रष्टाचार व काली कमाई, काली मुद्रा व काली सम्पत्ति का मूल उद्दम शत प्रतिशत नकदी आधारित मौद्रिक व्यवस्था में निहित है। नकद मुद्रा का कोई रंग नहीं होता है, परन्तु इसका अबोध प्रयोग करवंचन के माध्यम से काली मुद्रा के सृजन में होता है। यह नकद मुद्रा जब बिना कर चुकाये व रिकार्ड में लाये बिना सम्पत्ति, सोना–चाँदी, जवाहरात अवैधानिक व्यापार व उत्पादन में लगाई जाती है तो काले धन का सृजन होता है। इस प्रकार के धन का उपयोग पुनः ऐसे धन के सृजन में ही नहीं होता है, वरन् यह अनेक अनुत्पादक उपभोग को प्रेरित करती है। एक ओर इस प्रकार के धन व सम्पत्ति के सृजन से सरकार वैधानिक करों के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होती है। इस आय का उपयोग सरकार जनहित व विकास के कार्यों में प्रयोग करने से वंचित हो जाती है। सरकार को व्यय करने की पूर्ति के अनेकानेक कर लगााने और करों की दरों को बढ़ाने के लिये विवश होती है। इसका भार सीधे–सीधे ईमानदारी के साथ कर चुकाने वालों को उठाना पड़ता है। जिससे कर भार असहाय हो जाता है। जैसे–जैसे कर व कर की दरें बढ़ती है काली मुद्रा काली कमाई व कालेधन का सृजन और तेजी से होने लगता है। इन सभी का परिणाम विकास में कमी, जन सुविधाओं यथा शिक्षा,स्वास्थ्य आदि के अभाव गरीबी व बेरोजगारी के विस्तार व आर्थिक असमानताओं में वृद्धि के रूप में प्रकट होता है। यह समान्तर व्यवस्था शनैः–शनैः इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि कोई भी चुनी हुई सरकार इसे नियंत्रित करने की चाहे कितनी भी घोषणा क्यों न करे, कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं कर पाती है।

नकद की वर्तमान कमी से पीड़ित जनसाधारण को डिजिटल भुगतान के लिये तैयार करने में अनेक बाधायें बतायी जाती है। जनसंख्या के बड़े भाग का अशिक्षित होना,इंटरनेट के उपयोग की सुविधा नहीं होना, इन भुगतान के लिये तकनीक की जानकारी नहीं होना आदि–आदि प्रमुख बाधायें बताई जाती है, यह सही है, नकद रूप में भुगतान करना सरलतम है,और किसी भी आवश्यकता

या आपात स्थिति का सामना नकद द्वारा किया जा सकता है। इन सभी कठिनाईयों के बावजूद देश का भावी आर्थिक विकास व समृद्धि भुगतान व्यवस्था के परिवर्तन में छिपी है। अशिक्षित व अप्रशिक्षित इसी जनसाधारण ने प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद मोबाइल फोन तकनीक को अपनाया। अल्पकाल में ही देश में टेलीफोन का घनत्व व प्रयोग तेजी से बढ़ा है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक अनिवार्यता बन गया है। यही वह प्रेरणा है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बहुत शीघ्र ही जनस्वीकार्य बनायेगी। इसका अभिप्राय यह है बिल्कुल नहीं कि देश में नकद भुगतान पूर्णतः रूक जायेगा। विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नकद भुगतान उल्लेखनीय सीमा तक होता है। भारत का भी लक्ष्य है कि कम नकद के उपयोग वाली भुगतान व्यवस्था को अपनाया जाय।

उद्देश्य

आज मानवाधिकार की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गयी है। मानव अधिकार आंदोलन की उपादेयता तभी है, जब समाज से सभी प्रकार के भेदभाव का अन्त हो। किन्तु वर्तमान राजनैतिक तंत्र इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। आज भी भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर मानवाधिकार की विभिन्न समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में बुद्धिजीवियों,साहित्यकारों, राजनेताओं, मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों के सार्थक चिन्तन, मनन एवं गंभीर विचारों को रखा गया है जिसमें विश्व की गंभीर समस्या मानव अधिकारों के हनन एवं सरंक्षण की दशा, दिशा एवं इसका भावी समाधान कैसे हो? इस पर प्रकाश डाला गया है तथा मानव अधिकारों के प्रति जनता ज्यादा जागरूक हो एवं प्रशासन भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। यही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था क्यों जरूरी हैं

विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने लोगों को कैशलेस लेनदेन करने के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लेनदेन कैशलेस हो ताकि कालेधन और गैर कानूनी धंधों पर रोक लगे, इसका सीधा सा अर्थ हैं कि लोग भुगतान एवं कोषों का हस्तान्तरण के लिए यू.पी.आई.पेमेन्ट, ई–वॉलेट, प्रीपेड, डेबिड और क्रेडिट कार्ड आधार लिंक्ड भुगतान यू.एस.एस.डी. को ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में लाये। कालेधन के सृजन को स्थायी रूप से समाप्त करने के भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ने के लिये सम्पूर्ण विश्व में भुगतान के लिये डिजिटल व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिये व्यापक आर्थिक सुधार जिनमें वस्तु व सेवा का प्रमुख है, के कार्यक्रम अपनाने के साथ–साथ डिजिटल भुगतान व्यवस्था को प्रेरित कर रहा है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिये अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, डिजिटल भुगतान में आने वाले व्यय को धीरे–धीरे समाप्त करने के प्रयास हो रहे है। जैसे –जैसे जनसाधारण इनका अभ्यस्त होता जायेगा, इन भुगतानों का दायरा बढ़ाया जायेगा। बैंकिंग व्यवस्था भी सरलतम, सर्वस्वीकार्य एवं सस्ते भुगतान माध्यम को विकसित करने में लगा है।

नकद का बाजार में ज्यादा प्रचलन होने से होने वाली समस्याओं जैसे :– जाली नोटों का अधिक चलन में होना दूसरा अनुमान से अधिक कालाधन जमा होना। दोनों कारणों से एक समान्तर अर्थव्यवस्था निर्माण हो जाता हैं, जिसके चलते अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है तथा समाज में असंतोष पैदा होता हैं अतः निम्न कारणों से कैशलेस अर्थव्यवस्था जरूरी हैं:–

1. नकद के अत्यधिक चलन में होने से जाली नोटों की भरमार एवं बेहिसाब बढ़ोतरी से यह धन नक्सलवाद, आतंकवाद और माफियाओं के द्वारा अपनाएं जाने से राज्य में विद्रोह और अपराधिक गतिविधियां बढ़ती जाती है इसे रोकने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था का होना जरूरी हो जाता है।
2. किसी भी देश की नकदी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसी देश की एक बड़ी भारी पूंजी व्यय होती है। प्रति वर्ष नकदी पुरानी होती जाती है तथा इसकी पूर्ति फिर नई नकदी छापनी पड़ती है। यदि नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
3. कैशलेस लेनदेन से ए.टी.एम. के संचालन पर होने वाली लागतों से बचा जा सकता हैं क्योंकि वर्तमान में लोगों द्वारा ए.टी.एम. अधिक उपयोग किये जा रहे है।
4. जाली या नकली करेन्सी के बाजार में चलन की समस्या के रोकथाम में सहायता, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार बाजार में प्रचलन 7 नोटों में से एक नोट के जाली होने की संभावना रहती है।
5. कैशलेस लेनदेन स्वास्थ्यकारी होता है क्योंकि नोटों का एक हाथ से दूसरे हाथों में चलन के कारण जाने अनजाने में दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।
6. लागतों में कमी कर बचतों का समाज कल्याण में अधिक से अधिक उपयोग संभव होगा।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के अनेक फायदे हैं जिनमें कुछ इस प्रकार ह

आधुनिक बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था

कालेधन और भ्रष्टाचार की समस्याओं की वजह से सरकार ज्यादा इनकम टैक्स संग्रह नहीं कर पाती है। सरकार के इनकम टैक्स का बड़ा स्त्रोत नौकरीपेशा वाले शक्स है जबकि कारोबारी समुदाय अपनी आय छुपाने में काफी हद तक कामयाब हो जाते है। जब लोगों के आय व्यय की जानकारी ऑनलाइन हो जायेगी तो सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार को टैक्स वसूलने में सहूलियत होगी।

ई–कॉमर्स को बढ़ावा

कैशलेस अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक फायदा ई–कॉमर्स को पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था का यह ढ़ांचा इंटरनेट पर निर्भर है। यही वजह हैं कि ई–सेक्टर में भारी बढ़ोतरी होगी। डिजिटल भुगतान परोक्ष रूप से नोटों और उसके परिवहन में आ रहे व्यय को कम करने में भी सहायक होगा। लेन–देन की प्रकिया में पारदर्शिता आएगी।

आतंकवाद और जाली नोटों का होगा खात्मा

कैशलेस अर्थव्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें नकली या जाली नोट बाजार से समाप्त हो जाते है। साथ ही आतंकवाद के समापन में भी सहायक हैं क्योंकि आतंकवादी अधिकतर नकद रकम का प्रयोग करते है।

भ्रष्टाचार में कमी

कैशलेस अर्थव्यवस्था की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। डिजिटल भुगतान होने से पैसे की ट्रांसफर की सूचना आसानी से लगायी जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों ने कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाई है वहां भ्रष्टाचार बेहद कम है।

भारत के डिजिटलीकरण में तेजी

सम्पूर्ण भारत में लोगों को इन्टरनेट के द्वारा जोड़ने का अभियान डिजिटल इंडिया चल रहा है। इसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर कर दिया जाए। कैशलेस अर्थव्यवस्था डिजिटल होने के कारण भारत के डिजिटलीकरण में तेजी आएगी।

बैंकों के पास विकास के लिए अधिक पूंजी

कैशलेस अर्थव्यवस्था से बैंकों के पास अधिक पूंजी होगी। जिसे प्राइवेट सेक्टर में निवेश किया जा सकेगा। इसे विकास मूलक कार्यों, परियोजनाओं में लगाया जा सकता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में बैकिंग और टैक्स व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो जाने से बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार हो जायेगा ।

घर बैठें वित्तीय प्रबंधन

कैशलेस अर्थव्यवस्था का यह फायदा हैं कि आप अपने सारे वित्तिय प्रबंधन जैसे खरीददारी, बिल के भुगतान, टिकट बुकिंग आदि घर बैठे या ऑफिस से कर पाने में सक्षम होंगे।

आर्थिक समावेश

कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानूनों पर निगरानी रख सकती है। छोटे जगहों पर जहां बैंकिंग की सुविधा नहीं हैं, वहां आसानी से ई–पेमेंट व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की जा सकती है। कल्याणकारी योजनाओं का फंड सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जा सकता है।

भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने में आने वाली चुनौतियाँ

1. इन्टरनेट संचार सुविधाओं में कमी तथा लोगों में वित्तीय साक्षरता का अभाव।
2. जनधन योजना में लगभग 26.03 करोड़ खाते खोले गए खातों में से अधिकतर खातों का गैर संचालन होने के कारण लोगों के एक समूह का कैशलेस लेनदेन करने से वंचित रहने की संभावना बनी रहेगी इसलिए इन खातों के संचालन हेतु लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
3. लोगों की सोच हैं कि नकद लेनदेन के द्वारा मोलभाव किया जा सकता है भले ही इसमें कितनी भी परेशानी उठानी पड़े अतः लोगों को भुगतान के डिजिटल माध्यमों से होने वाली सुविधाओं की अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
4. इन्टरनेट के माध्यम से होने वाली सुरक्षा कारणों में हैकिंग की समस्याओं के कारण भी लोगों द्वारा कैशलेस व्यवहार नहीं किये जाते है अतः डिजिटल लेनदेन को उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जावे।
5. अधिकतर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड धारक यह सोचते हैं कि यदि ज्यादा ये ज्यादा लेनदेन इन कार्डों के द्वारा किया जायेगा तो बैंक द्वारा अधिक चार्ज वसूलें जायेगे जिससे वे नोटों द्वारा भुगतान या कोई भी लेनदेन नियमित करते है अतः लोगों को बैंकों द्वारा कम से कम चार्ज किये जाएँ।
6. आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली की नियमित आपूर्ति का नहीं होना ।
7. गाँवों में जनसंख्या का 70 प्रतिशत जनसमूह निवास करता है जिनमें से काफी लोग निरक्षर है अतः कैशलेस के माध्यम में सहायक तकनीक का ज्ञान करना अपने आप में एक समस्या है।

डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपनाने का मुख्य औचित्य

यह है कि इस व्यवस्था से सम्पूर्ण जीडीपी का रिकार्ड उत्पादन, वितरण व आय के रूप में रखा जाना संभव हो सकेगा। इस व्यवस्था में करवेचन अत्यन्त कठिन हो जायेगा। जिससे कर–सुधारों को आसानी से अपनाया जा सकेगा। कर भार कम हो सकेगा और सरकार को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगे। सरकार इंफ्रास्ट्रकचर पर अधिक संसाधन लगाकर विनियोगों विशेषकर निजी विनियोगों को प्रेरित कर सकती है। इससे गरीबी को तेजी से कम करना,रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना संभव हो सकेगा। समाज में बढ़ती आर्थिक व अवसरों की असमानताओं को नियंत्रित करना संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

भारत एक विशाल देश हैं जहा पर अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है। कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू करने में कठिनाईयां आना स्वभाविक है परन्तु इस दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी था। आज कैशलेस अर्थव्यवस्था भारत के विकास दर में अच्छी प्रगति के लिए अति आवश्यक थी। देश लेनदेन की आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और इस कारण डिजिटल भुगतान व्यवस्था में वृद्धि हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Jain, P.M.(2006).E-payment and E-Banking. indian Banker,March p.p.108-113.*
2. *Bureau,The Fature of E-commerce is bright, Business line.*
3. *Demonetizationhttp://www.investopedia.com/trems/d/demonetization.as#xzz4QRacCuLL.*
4. *राजस्थान पत्रिका*